खनन में चार गुना बढ़ा राजस्व 12 सौ करोड़ के पार पहुंचा

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून : उत्तराखंड में अवैध खनन पर सख्ती और पारदर्शी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य के खनन राजस्व में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। खनन व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाए जाने के चले डेढ़ वर्ष से भी कम समय में राज्य का वार्षिक खनन राजस्व 300 करोड़ रुपये से चार गुना बढ़कर 1200 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। प्रदेश में खनन सरकार के राजस्व का प्रमुख जरिया रहा है। यद्यपि, पूर्व में इस ओर बहुत अधिक ध्यान न दिए जाने के कारण इससे अपेक्षित राजस्व नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तकरीबन दो वर्ष पूर्व खनन को तकनीकी से जोड़ते हुए अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए आधुनिक

- खनन गतिविधियों को आधुनिक तकनीक से जोडऩे का विभाग को मिला है लाभ
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के कारण दो वर्ष में हुआ वदलाव

व्यवस्था अपनाई। इसके लिए सितंबर, 2024 में प्रदेश में नई खनन नीति लागू की गई, जिसके तहत खनन लाट का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है।

खनन में चार गुना बढ़ा राजस्व 12 सौ करोड़ के पार पहुंचा

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून : उत्तराखंड में अवैध खनन पर सख्ती और पारदर्शी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य के खनन राजस्व में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। खनन व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाए जाने के चले डेढ़ वर्ष से भी कम समय में राज्य का वार्षिक खनन राजस्व 300 करोड़ रुपये से चार गुना बढ़कर 1200 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

प्रदेश में खनन सरकार के राजस्व का प्रमुख जरिया रहा है। यद्यपि, पूर्व में इस ओर बहुत अधिक ध्यान न दिए जाने के कारण इससे अपेक्षित राजस्व नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तकरीबन दो वर्ष पूर्व खनन को तकनीकी से जोड़ते हुए अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए आधुनिक व्यवस्था अपनाई। इसके लिए सितंबर, 2024 में प्रदेश में नई खनन नीति लागू की गई, जिसके तहत खनन लाट का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगा है।

नई नीति के तहत खनन गतिविधियों की उपग्रह आधारित निगरानी, खनन परिवहन के लिए माइनिंग सर्विलांस प्रणाली, डिजिटल ट्रैकिंग और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की, जिससे अवैध गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। सितंबर, 2024 से पहले राज्य को खनन से लगभग 300 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होता था, जो अब बढ़कर 1200 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। खनन सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड को देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस कारण केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता स्वीकृत की है।

> प्रदेश में आमजन के आवासीय निर्माण और विकास परियोजनाओं के लिए खनन सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसे पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप और पारदर्शी व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है। खनन से प्राप्त राजस्व का उपयोग जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन और राज्य के विकास कार्यों में किया जा रहा है।
>
>
>
> -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड